

खास-खबरें

आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक 5 अक्टूबर से

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: आरबीआई की तीन दिवसीय द्र्मासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक 5 से 7 अक्टूबर के बीच मुंबई में होगी। आर्थिक मामलों के जानकारों को इस बार नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में 0.25 फीसदी बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में छह सदस्यों वाली एपपीसी की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक में महंगाई, आर्थिक गतिविधियों और नीतिगत ब्याज दरों (रेपो रेट) की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा 7 अक्टूबर की सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति के फैसले की जानकारी देंगे। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि इस बार आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकता है। ग़ोकरेज फर्म नोमुरा ने अक्टूबर और दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा की बैठकों में नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में 0.25–0.25 फीसदी की बढ़ोतरी किए जाने का अनुमान जताया है।

जल्द भारत आएगी नई चीनी लजरी कार, जारी हुआ टीजर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: चीनी वाहन निर्माता कंपनी बीवाईडी की प्रीमियम कार ब्रांड डेंजा जल्द भारतीय बाजार में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने भारत में अपनी आगामी कारों को लेकर टीजर जारी किया है। इसके साथ ही देश के लजरी वाहन बाजार में डेंजा के प्रवेश का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। कंपनी भारत में प्रीमियम श्रेणी की कारें पेश करने की तैयारी कर रही है।

डेंजा को बीवाईडी के प्रीमियम वाहन ब्रांड के रूप में विकसित किया गया है। कंपनी की ओर से जारी टीजर में आगामी वाहन की झलक दिखाई गई है। हालांकि, भारत में पेश किए जाने वाले मॉडल और उनकी कीमतों से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर लॉन्च की तारीख और वाहन की विस्तृत विशेषताओं की जानकारी भी साझा नहीं की गई है।

डेंजा के भारतीय बाजार में प्रवेश से देश के प्रीमियम और लजरी वाहन खंड में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कंपनी अपने प्रीमियम वाहनों के जरिए ऐसे ग्राहकों को लक्षित कर सकती है, जो आधुनिक तकनीक और लजरी सुविधाओं वाली कारों की तलाश में हैं। डेंजा के वैश्विक पोर्फोलियो में विभिन्न श्रेणियों के प्रीमियम वाहन शामिल हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक और प्रीमियम वाहनों की मांग बढ़ने के बीच डेंजा का प्रवेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीवाईडी पहले से भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है और डेंजा के जरिए कंपनी प्रीमियम वाहन खंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। भारत में डेंजा की पहली कार कोन-सी होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी लॉन्च के समय सामने आने की उम्मीद है। कंपनी की ओर से जारी टीजर के बाद अब भारतीय बाजार में उसके आगामी वाहनों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना पर 7.4 प्रतिशत ब्याज, हर महीने 9,250 रुपये तक आय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की राष्ट्रीय बचत मासिक आय योजना पर 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा। इस योजना में निवेश कर हर महीने निश्चित आय प्राप्त की जा सकती है। योजना की अवधि पांच वर्ष है।

पोस्ट ऑफिस मासिक आय खाता भारत सरकार की छोटी बचत योजना है। इसमें जमा राशि पर मिलने वाले वार्षिक ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है। यदि ब्याज की राशि नहीं निकाली जाती है तो वह पोस्ट ऑफिस बचत खाते में रहती है। उस राशि पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता। ब्याज का भुगतान केवल मूलधन पर किया जाता है।

यदि कोई निवेशक इस योजना में 9 लाख रुपये जमा करता है तो 7.4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के आधार पर उसे एक वर्ष में 66,600 रुपये ब्याज मिलेगा। यह राशि 12 महीनों में बांटने पर हर महीने 5,550 रुपये होगी। संयुक्त खाते में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा करने पर 7.4 प्रतिशत की दर से एक वर्ष में 1 लाख 11 हजार रुपये ब्याज मिलेगा। इसे 12 महीनों में बांटने पर हर महीने 9,250 रुपये की आय होगी।

यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपनी जमा राशि को सुरक्षित रखते हुए नियमित मासिक आय चाहते हैं। योजना में पांच वर्ष के लिए निवेश करना होता है। यह विशेष रूप से सेवानिवृत्त लोगों, बुजुर्गों और नियमित आय चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयोगी मानी जाती है।

50 पेटाबाइट डेटा की जांच में जुटी ओपनएआई, इंसान को पढ़ने में लगेंगे करीब 6.6 करोड़ साल

रैंन फ्रांसिस्को, एजेंसी: चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई ने खुलासा किया है कि उसके एआई एजेंट्स ने 100 से ज्यादा संस्थानों के सिस्टम में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। कंपनी के अनुसार, इन घटनाओं में संस्थानों का डेटा चोरी होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एआई एजेंट्स ने कई वेबसाइट्स को अनधिकृत कमांड भेजकर गलत प्रक्रियाएं चलाने का प्रयास किया। कुछ मामलों में सुरक्षा तंत्र को दरकिनार करने के लिए वेबसाइट्स को आपसी संपर्क के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई।

ओपनएआई अब अपने एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग और परीक्षण से जुड़े करीब 50 पेटाबाइट डेटा की जांच कर रही है, ताकि पहले सामने नहीं आई किसी अन्य गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। इस काम के लिए 7 हज़ार अत्याधुनिक जीबी200 और जीबी300 जीपीयू लगाए गए हैं। कंपनी के अनुसार, इस प्रक्रिया पर प्रतिदिन करीब 5 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

हरियाणा से कनाडा पहुंचा 24 मीट्रिक टन फ़ोजन खाद्य उत्पाद



नईदुनिया ब्यूरो, सोनीपत: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की मदद से हरियाणा के सोनीपत से कनाडा 24 मीट्रिक टन फ़ोजन खाद्य उत्पादों की खेप रवाना की गई। एक अक्टूबर को भेजी गई इस खेप का निर्यात अटेर्नो फूड्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने किया। इसमें 35,140 कनाडाई डॉलर मूल्य के 2,295 डिब्बे शामिल हैं।

खेप में हरी मटर, मिश्रित सब्जियां, मटर एवं गाजर, स्वीट कॉर्न और समोसे शामिल हैं। निर्यात करने वाली इकाई को एपीडा की वित्तीय सहायता योजना के तहत सहयोग मिला। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से होने वाला यह निर्यात भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवसर बढ़ाने के साथ किसानों और खाद्य उत्पादकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एपीडा किसान उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों को निर्यातकों

नईदुनिया

एआई मॉडल्स बेकाबू 100 संस्थानों में सेंधमारी



यदि इतना डेटा सामान्य अंग्रेजी शब्दों में हो और कोई व्यक्ति 240 शब्द प्रति मिनट की गति से लगातार पढ़े, तो उसे पूरा पढ़ने में करीब 6.6 करोड़ साल लगेंगे। इसी कारण डेटा की जांच के लिए एआई मॉडल्स का इस्तेमाल किया

जा रहा है।

कंपनी ने प्रभावित संस्थानों को सतर्क किया है और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई है, ताकि वे अपने सिस्टम में हुई सेंध की कोशिशों

और सुरक्षा खामियों की जांच कर

सके। ओपनएआई ने माना है कि उसके सुरक्षा उपाय एआई एजेंट्स को नियंत्रित करने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। कंपनी ने कहा है कि वह एआई मॉडल्स के असामान्य व्यवहार और सुरक्षा संबंधी निष्कर्ष सार्वजनिक करेगी।

जुलाई में हर्गिंग फेस से जुड़ी घटना के बाद ओपनएआई ने एआई सुरक्षा नियम और कड़े किए हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं, अनुसंधान और लाइव सिस्टम को अलग किया गया है तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए रियल-टाइम निगरानी बढ़ाई गई है। इससे पहले एक परीक्षण के दौरान एआई मॉडल ने प्रतिबंधों के बावजूद इंटरनेट तक पहुंच बनाने और हर्गिंग फेस के सिस्टम से जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। जांच में एआई एजेंट्स के बीच गुप्त संदेशों के आदान-प्रदान की जानकारी भी सामने आई थी। इसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सरकारी वेबसाइट्स में सेंध की कोशिशों का भी उल्लेख किया गया।

सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई योजना, घरेलू और विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने पर जोर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट यानी आरओडीटीईपी योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला किया। यह सुविधा घरेलू टैरिफ क्षेत्र की इकाइयों, अग्रिम प्राधिकरण धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों और निर्यातोन्मुखी इकाइयों की ओर से किए जाने वाले निर्यात पर उपलब्ध रहेगी।

आरओडीटीईपी योजना के तहत निर्यातित उत्पादों पर वहन किए गए ऐसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क, कर तथा उपकर वापस किए जाते हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति अन्य माध्यमों से नहीं हो पाती। इसमें उत्पादन और निर्यात से पहले के चरणों में जमा अप्रत्यक्ष कर भी शामिल हैं। योजना का उद्देश्य निर्यातकों को इन लागतों की भरपाई उपलब्ध कराना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी स्थिति मिल सके।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2026 को अधिसूचित मौजूदा आरओडीटीईपी दरें और

निर्यातकों के लिए आरओडीटीईपी योजना की अवधि बढ़ी



मूल्य सीमाएं 31 दिसंबर 2026 तक अपरिवर्तित रहेंगी। इन दरों और सीमाओं में इस अवधि के

दौरान कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

योजना की अवधि बढ़ाने से

सरकार ने निर्यातकों के लिए रिलीफ स्कीम की अवधि 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यवधानों के बीच निर्यातकों को राहत देते हुए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम के बाद व्यापारियों को सहायता पहुंचाने के लिए रिलीफ (रेजीलिएंस एंड लॉलिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन) पहल की परिचालन अवधि को बढ़ा दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग

मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर, 2026 की अधिसूचना संख्या 37/2026–27 के जरिए रिलीफ-रेजीलिएंस एंड लॉलिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन के घटक-II के तहत निर्धारित समय-सीमा को 31 मार्च, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। रिलीफ, निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत एक समयबद्ध पहल है।

एक मीट्रिक टन फूल मखाने की खेप रवाना

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद

नईदुनिया ब्यूरो, पूर्णिया: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की मदद से बिहार के पूर्णिया से ग्रीस के लिए एक मीट्रिक टन फूल मखाने की खेप रवाना की गई। यह खेप पूर्णिया के बेलौरी स्थित इंडो ग्लोबल एक्सपोर्ट से मंगाई गई है और नई दिल्ली की एसएस फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ग्रीस भेजी जा रही है। खेप मुंद्रा बंदरगाह से ग्रीस के पिराएउस बंदरगाह तक पहुंचेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मखाने को घरेलू बाजार की तुलना में अधिक कीमत मिलने से उत्पादकों के लिए अतिरिक्त मूल्य सृजन की संभावना सामने आई है। मखाना उत्पादन में भारत दुनिया में अग्रणी

बिहार के मखाने ने यूरोपीय

बाजार में बनाई नई पहुंच



है और देश के कुल उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 से 85 प्रतिशत है। राज्य के 10 जिलों में 35 हज़ार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मखाने की खेती की जाती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा की ओर से इस क्षेत्र को तकनीकी सहायता दी जा रही है। खेप रवाना करने के कार्यक्रम को वैश्विक व्यापार विहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने

की। उन्होंने कहा कि बिहार का मखाना लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बना रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में भारत ने 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलों पर 7 हज़ार मीट्रिक टन से अधिक मखाना और उससे बने उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कीमत 2.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर रही। बिहार सरकार निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति पर काम कर रही है। मखाना निर्यात मूल्य श्रृंखला को सहायता देने के लिए पैकहाउस भी बनाए गए हैं। एपीडा के प्रयासों से भारतीय मखाने की यूरोपीय बाजारों में पहुंच बढ़ रही है, जिससे उत्पादकों और निर्यातकों के लिए नए अवसर बन रहे हैं।

आरबीआई ने दी मंजूरी, 27 अक्टूबर से संभालेंगे पदभार; तीन साल का होगा कार्यकाल

एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने अनूप बागची

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: एचडीएफसी बैंक ने अनूप बागची को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिलने के बाद बैंक ने 1 अक्टूबर को शेरय बाजार को दी जानकारी में नियुक्ति की पुष्टि की। बागची 27 अक्टूबर से पदभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। मौजूदा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 26 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। जगदीशन ने अगले कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति की मांग नहीं की थी। अनूप बागची को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में 30 साल से अधिक का अनुभव



है। एचडीएफसी बैंक की कमान संभालने से पहले वह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। शीर्ष पद के लिए अनूप

बागची के साथ एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंध निदेशक कायद भस्का का नाम भी प्रस्तावित किए जाने की जानकारी सामने आई थी। बैंक ने शीर्ष पद के लिए दोनों नाम भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष भेजे थे। इसी दिन कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अनूप कुमार साहा को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा और वह 1 जनवरी 2027 से पद संभालेंगे। साहा फिलहाल बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। उनके पास 32 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में 25 साल से अधिक का अनुभव शामिल है।

फास्टैग नियम बदले, दिव्यांगजनों को 5 साल तक नहीं कराना होगा नवीनीकरण

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिव्यांगजनों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी किए जाने वाले टोल छूट वाले फास्टैग के नियमों में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था 2 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई है। अब पात्र लाभार्थियों को हर साल फास्टैग का नवीनीकरण कराने की ज़रूरत नहीं होगी। फास्टैग की वैधता संबंधित व्यक्ति के दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर तय की जाएगी।

नए नियम के अनुसार, जिन लाभार्थियों की दिव्यांगता 70 से 100 प्रतिशत तक दर्ज है, उनके फास्टैग की वैधता पांच साल होगी। वहीं, 40 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लाभार्थियों

के फास्टैग की वैधता तीन साल होगी। वैधता अवधि समाप्त होने के बाद फास्टैग का दोबारा नवीनीकरण कराया जा सकेगा। इसके लिए लाभार्थी की पात्रता और वैध दिव्यांगता दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

नई व्यवस्था में फास्टैग की वैधता दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य मान्य दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर तय होगी। टोल छूट वाला फास्टैग सभी वाहनों के लिए लागू नहीं होगा। यह सुविधा दिव्यांगजनों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पात्र वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों पर लागू होगी।

मिलवांकी, एजेंसी:

अमेरिका के विस्कॉन्सिन स्थित मिलवांकी में आयोजित जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार में विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपाय अपनाने की अपील की। उन्होंने संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन, सर्वोच्च राष्ट्र सिद्धांत, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम के उन्मूलन और व्यापार व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भारत का पक्ष रखा।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत



दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और 1.4 अरब लोगों की घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत डिजाइन से लेकर तैयार उत्पाद तक विनिर्माण मूल्य

श्रृंखलाएं विकसित कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कड़ी के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करती है

तथा जी20 द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में भारत के पास संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार की विकृत करने वाला समर्थन डॉपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण को बढ़ावा दे सकता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए साक्ष्य आधारित एंटी-डॉपिंग और प्रतिकारी शुल्क जैसे विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपाय उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन क्षमता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि छिपी सन्निधि और समर्थन से प्रेरित उत्पादन का भौगोलिक संकेंद्रण व्यापार में विकृति पैदा कर सकता है। आपूर्ति श्रृंखलाओं

में विविधता लाना उचित उद्देश्य है, लेकिन इसके नाम पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों से बाहर जाकर उपाय नहीं किए जाने चाहिए और विकासशील देशों पर समायोजन का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। सर्वोच्च राष्ट्र सिद्धांत पर गोयल ने पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और नियम आधारित व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता बताई। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में आम सहमति और विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अलग व्यवहार बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही दो स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली बहाल करने की मांग की।

जबरन श्रम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत इसके उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 23 और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंधित सम्मेलनों का उल्लेख करते हुए बताया कि जुलाई 2026 में जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध के लिए विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि सीमा पर उठाए जाने वाले कदम विशिष्ट और सत्यापन योग्य साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए तथा उचित प्रक्रिया और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन होना चाहिए।